निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या 04 वर्ष 2017-18

यह निरीक्षण प्रतिवेदन **महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र, रूद्रपुर (उधमसिंह नगर)** द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय **महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र, रूद्रपुर (उधमसिंह नगर)** के माह 04/2012 से 04/2017 तक के लेखा अभिलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री एस.एस. दरियाल,सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी, श्री मनोज कुमार सिंह, पर्यवेक्षक एवं श्री जितेन्द्र तमोली, लेखापरीक्षक द्वारा दिनांक 18/05/2017 से 23/05/2017 तक श्री अनिल कुमार जैन वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित किया गया।

भाग-I

1. **परिचयात्मकः** इस इकाई की विगत लेखापरीक्षा श्री पी.के. गुप्ता एवं श्री शशि कुमार, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारियों तथा श्री दिनेश कुमार, पर्यवेक्षक द्वारा दिनांक 21/06/2012 से 29/06/2012 तक श्री ए.के. भारतीय, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित की गयी थी। जिसमें माह 04/2010 से 03/2012 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी थी।
2. (i) इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्रः उद्योग को बढ़ावा हेतु राज्य एवं केन्द्रीय नितियों का क्रियान्वयन, सम्पूर्ण जिला।

(ii) (अ) विगत पांच वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः

वर्ष	प्रारम्भिक अवशेष		स्थापना		गैर स्थापना		अवशेष			
							स्थापना		गैर स्थापना	
	स्थापना `	गैर स्थापना `	आवंटन `	व्यय `	आवंटन `	व्यय `	आधिक्य (+) □	बचत (-) □	आधिक्य (+) □	बचत (-) □
2012-13			17576622	17072733	3371000	3371000				
2013-14			19692387	18229721	1373000	1373000				
2014-15			24132639	18870060	1870000	1870000				
2015-16			19902638	19050383	819000	819000				
2016-17			19228000	18653119	570000	570000				

(ब) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत हैः

वर्ष	योजना का नाम	प्रारम्भिक अवशेष `	प्राप्त `	व्यय अधिक्य (+) `	बचत (-) `
बजट प्राविधान नहीं है। सिड़कुल को आवंटित तथा वितरित की जाती है।					

(iii) इकाई को बजट आवंटन **राज्य सरकार** द्वारा किया जाता है। गैर स्थापना व्यय को सम्मिलित न करते हुए इकाई **C** श्रेणी की है। विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः

(iv) **लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः** लेखापरीक्षा में सम्पूर्ण जनपद, **महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र, रूद्रपुर (उधमसिंह नगर)** को आच्छादित किया गया। समस्त स्वाधीन आहरण एवं वितरण अधिकारियों के निरीक्षण प्रतिवेदन पृथक-पृथक जारी किये जा रहे है। यह निरीक्षण प्रतिवेदन **महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र, रूद्रपुर (उधमसिंह नगर)** की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। माह 12/2012, 08/2013, 03/2014, एवं 12/2016 को विस्तृत जांच हेतु चयनित किया गया। **10/2015 एवं 09/2014** का विस्तृत विश्लेषण किया गया। प्रतिचयन अधिकतम मासिक व्यय के आधार पर किया गया।

(v) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा 13, लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

Hkkx nks ¼v½

izLrj 1- :0 30 yk[k dk dsUnzh; iwWath fuos"k lgk;rk dk vfu;fer Hkqxrku bdkbZ;ksa dks fd;k tkukA

As per the para 11 of Central Capital Investment Subsidy scheme,2003 if the central Government/State government concerned is satisfied that the subsidy or grant to an industrial unit has been obtained by misrepresentation as to an essential fact, furnishing of false

information the central government/state government may, after giving opportunity to the unit concerned of being heard, ask the unit to refund the grant or subsidy already received.

Further as para 14 after the receiving the grant or subsidy, each industrial unit shall submit Annual Progress Report to the State Government about its working for a period of 5 years after going into production.

As per Govt. of India guidelines/Instructions cash payment have not been considered. Plant&Machinery acquired after the registration and with-in one year from the date of commencement of commercial Production only has been considered. In bank finance cases fixed capital investment in plant& machinery as per bank appraisal has been considered as eligible for calculating CCISS. On the basis of the above, the amount of 15% subsidy to which you are entitled in determined at Rs. you are entitled in determined at Rs. 30.00 lakhs.

Government of India Ministry of Commerce & Industry Department of Industrial Policy & promotion (special Package Section) No.3(2)2008-SPS Dated 25th January 2011 sub:- Clarification on Grant of Central Capital Investment Subsidy to an Industrial Undertaking Company or Group setting up more than one unit in the state of Uttarakhand-regarding

that units located in the same khasra number/location/Industrial area would be eligible for the subsidy if they are separate and distinct and registered as such under the relevant State/Central Laws.

oSV vf/kfu;e 2005 dh /kkjk 3 dh mi/kkjk ¼2½ esa dgk x;k fd izR;sd O;fDr tks bl vf/kfu;e ds micU/kksa ds vUrxZr iathd`r gSA vFkok iath;u ;ksX; gS ,d djk/ks; O;fDr gksxk vkSj vf/kfu;eksa esa micfU/kr jhfr ds vUrxZr dj dk Hkqxrku djus ds fy;s nk;h gksxkA ;fn fdlh O;kSgkjh dh okf'kZd VZu vksoj :0 5-00 yk[k ls vf/kd gS rks mldksa okf.kT; dj foHkkx ls iath;u ysuk vfuok;Z gSA

M/s Polyplex Corporation Ltd. (Chips Unit) Vill. Vikrampur,Bazpur, distt U.S.Nager dh dsUnzh; iwWath miknku nkos ls lEcfU/kr i=koyh dk voyksdu djus ij ik;k x;k fd eSllZ iksyhlySDl dkiksZjs"ku fyfeVsM fdPNk esa o'kZ 31@03@1988 ls fuekZ.k ikSfyLVj fQYe rFkk fpll dk;Z djus ds fy;s okf.kT; dj foHkkx esa iathd`r gSA rFkk ftldh "kk[kk &cUuk[skMk jksM xzke fodzeiqjk rglhy cktiqj ?kksf'kr gSA ewy fofuekZrk QeZ }kjk viuk mRiknu fnukad 5@4@2007 ls izkjEHk ?kksf'kr fd;k x;k FkkA ftlds lkis{k i=kad la[;k 4174 fnukad 24@12@2008 dks dsUnzh; iwWath fuos"k lgk;rk 2003 ds vUrxZr :0 30-00 yk[k bdkbZ dks lgk;rk Lohd`fr iznku dh tk pqdh FkhA

bdkbZ }kjk ?kksf'kr czkUp dks CIS Registration No.569 fnukad 26@5@2010 esa iqu% ubZ bdkbZ dk ykHk izkIr djus ds fy;s dsUnzh; iwWath fuos"k lgk;rk 2003 essa iathdj.k djk;k x;k FkkA ftlesa ckzUp esa gq,s iwWath fuos"k ij 15 izfr"kr dh nj ls :0 30-00 dk nkok izLrqr fd;kA izLrqr nkok vfHkys[kksa dk ijh{k.k fd;s fcuk gh ckzUp dh nkok /kujkf"k :0 30-00 yk[k dks laLrqr dj funs"kky; esa Lohd`fr djus gsrq izsf'kr fd;k x;kA funs"kky; ds i=kad la[;k 2729@D.I.(V)-CIS/2012-13 fnukad 22 flrEcj 2012 }kjk mDr QeZ dh ckzUp tksfd izFke bdkbZ ds fy;s gh dk;Z djrh gSa] dks Hkh :0 30-00 yk[k dh dsUnzh; iwWath fuos"k miknku lgk;rk Lohd`r dj nh x;h FkhA tksfd Hkkjr ljdkj }kjk vf/klwpuk 2003 esa mYyf[kr izko|kuksa ,oa No.3(2)2008-SPS Dated 25th January 2011 dk Li'V mYy?kau FkkA

bl lEcU/k esa foHkkx ls iwNus ij crk;k x;k fd rF;ksa ,oa vkWdMks dh iqf'V dh tkrh gSa];Fkk"kh?kz mfpr dk;Zokgh dj lEizs{kk ny dks voxr djk fn;k tk;sxk

foHkkxh; mRrj ekU; ugh gS] ;fn foHkkx }kjk nkok izkIr vfHky[kksa ,oa dsUnzh; iwWath fuos"k lgk;rk 2003 esa mYyf[kr izko|kuksa dk vuqJo.k ,oa fnukad 25 tuojh 2011 esa Hkkjr ljdkj }kjk tkjh vkns"kk ftlesa Li'V dgk x;k fd dsoy ogh bdkbZ;kWa bl ;kstuk dk ykHk izkIr djus ds fy;s ik= gksxh] ftuds }kjk izFke bdkbZ ls fHkUu LFkku ij dkjksckj dks LFkkfir fd;k x;k gks]vkSj ftuds }kjk LVsV@lSUV`y foHkkxksa esa vius dkjksckj dks djus ds fy;s vyx ls iathd`r djk;k x;k gksA foHkkx }kjk ftl izFke bdkbZ dh ?kksf'kr ckzUp dks ubZ bdkbZ dk ik= ekuk x;k Fkk] og bdkbZ okf.kT; dj foHkkx esa

vyx ls dkjksckj djus ds fy, iathd`r ugh Fkh] cfYd bdkbZ }kjk viuh izFke bdkbZ ds iathdj.k izek.k&i= ij gh ;g ykHk izzkIr fd;k x;k FkkA rFkk bdkbZ dh ckzUp }kjk vfuok;Z :i ls izLrqr dh tkus okyh mRiknu fjiksVZ]vds{k.k fjiksVZ Hkh mRiknu frfFk ls 5 o'kksZ rd dh ugh nh x;h Fkh]tksfd dsUnzh; iwWath fuos"k lgk;rk 2003 esa mYyf[kr fu;eksa ds fo:} FkkA blfy;s izFke bdkbZ dh ckzUp dks Lohd`r dh x;h dsUnzh; iwWath fuos"k lgk;rk /kujkf"k :0 30-00 yk[k dh olwyh 10 izfr"kr C;kt lfgr izFke bdkbZ;kssa ls Hkw&jktLo dh HkkWafr djds jktdks'k esa tek fd;s tkus ;ksX; gSA

vr% izdj.k laKku esa yk;k tkrk gSA

भाग-दो " अ"

प्रस्तर 2- नियमानुसार वसूली की कार्यवाही न किये जाने के कारण रु. 61.05 लाख न वसूला जाना किया जाना

कार्यालय जिला उद्योग केंद्र, उधमसिंह नगर की लेखापरीक्षा के दौरान केंद्रीय उपादान योजना 2003 के अंतर्गत केंद्रीय पूंजी उपादान Rs 30.00 लाख मै0 M°A°K° (India) Chemicals Ltd°, Plot 27 A, Nand Nagar Industrial Estate, Mahuakheda ganj, Kashipur Udhamsingh Nagar को दिनांक 29-09-2011 को संवितरित किया गया था और दिनांक 17/11/2011 को ही इकाई के द्वारा बिद्युत बिच्छेदन करवा लिया था अर्थात उपादान प्राप्त करने के 02 माह पश्चात ही इकाई ने उत्पादन बंद कर दिया था, जबकि भारत सरकार की अधिसूचना 8 जनवरी 2003 के क्रमांक 11 के प्रावधानानुसार इकाई को कम से कम 5 वर्ष तक उत्पादनरत रहना होगा, कार्यालय उद्योग केंद्र के संज्ञान में होने बाद भी आतिथि तक वसूली की कार्यवाही नहीं की गई हैं। अतः उक्त प्रावधानानुसार भुगतान की गई उपादान की □ 30.00 लाख धनराशि मय ब्याज वसूला जाना था। इसे इंगित करने पर बिभाग ने उत्तर मे बताया कि " यथाशीघ्र वसूली हेतु पत्राचार कर सूचित की जाएगी"। बिभाग के उत्तर से स्पष्ट हैं कि बिभाग के द्वारा उल्लिखित अधिसूचनानुसार कार्यवाही की जाती तो धनराशि वसूल ली जाती। अतः नियमानुसार वसूली कि कार्यवाही न किये जाने के कारण रु. 61.05 न किये जाने का प्रकरण उच्चाधिकारियो के संज्ञान में लाया जाता हैं।

भाग- दो "ब"

प्रस्तर 1- नियमानुसार वसूली की कार्यवाही न किये जाने के कारण रु. 142.52 लाख न वसूला जाना।

महाप्रबंधक जिला उद्योग केंद्र, उधमसिंह नगर (रुद्रपुर) कार्यालय के लेखापरीक्षा के दौरान औधोगिक ईकाइयो को भुगतान किए गए परिवहन उपादानो के दावो से संबन्धित पत्रावलियों की जांच मे पाया कि बिभिन्न औद्योगिक इकाइयो के परिवहन दावों पर सतर्कता

बिभाग द्वारा की गई जांच में मै0 चीमा पेपर मिल प्रा0लि0 बाजपुर, मै0 जिंदल वनस्पति उद्योग प्रा0लि0 काशीपुर, मै0 इंडिया ग्लाइकोल लि0 बाजपुर रोड काशीपुर, मै0 जिंदल वेजीटेबल प्रॉडक्ट प्रा0लि0 काशीपुर, मै0 एस0के0 पैकिंग इंड0 काशीपुर एवं मै0 उत्तराखंड ऑइल मिल को परिवहन उपादान दिया गया था, भुगतान की गई परिवहन उपादान की धनराशि फर्जी अभिलेख के आधार पर प्राप्त किये जाने की शिकायत पर सतर्कता विभाग द्वारा जांच कर, जाँच प्रतिवेदन शासन को उपलब्द कराई गयी थी, जिसमे फर्जी / मिथक परिवहन अभिलेखो/साक्ष्यों के आधार पर Rs 25,36,282.00 उपादान प्राप्त किया जाना पाया गया| (विवरण संलग्न) जिसके तारतम्य मे उत्तराखंड शासन एवं निदेशालय द्वारा प्रश्नगत धनराशियाँ 18% ब्याज सहित वसूले जाने हेतु इस कार्यालय को आदेशित किया गया था, लेकिन आतिथि तक उल्लिखित 6 इकाइयो मे से 2 इकाइयो से मात्र Rs 3,03,023.00 ही वसूला गया है अर्थात (Rs 25,36,282.00 - Rs 3,03,023.00) Rs 22,33,259.00 परिवहन उपादान की मूल धनराशि एवं 31-03-2017 तक आगणित ब्याज Rs 1,20,18,724.06 वसूला जाना शेष है अर्थात (Rs 22,33,259.00 + Rs 1,20,18,724.06) Rs1,42,51,983.10 वसूला जाना है|(विवरण पत्र संलग्न) इस संबंध मे शासन द्वारा उद्योग निदेशालय को और निदेशालय द्वारा 2005 से 2013 तक उल्लिखित इकाइयो से वसूली हेतु कार्यालय महाप्रबंधक को आदेशित किया था, जिसमे स्पष्ट आदेश था कि इकाई द्वारा धनराशि जमा न करने पर वसूली राजस्व विभाग के माध्यम से किया जाए लेकिन इस कार्यालय द्वारा आतिथि तक वसूली हेतु राजस्व विभाग को पत्राचार नहीं किया गया है। इसे इंगित करने पर विभाग ने उत्तर में बताया कि *"वसूली प्रमाणपत्र जारी करने हेतु जिलाधिकारी को पत्राचार कर सूचित किया जायेगा।"* जिसके तारतम्य में कार्यालय, महाप्रबंधक द्वारा इकाइयो को दिनांक 27/05/2017 (लेखापरीक्ष्यापरांत) को वसूली हेतु पत्र जारी किया है, इससे स्पष्ट है कि वसूली हेतु यथोचित कार्यवाही नहीं की गई थी जिस कारण रु.142.51 लाख की वसूली नहीं की जा सकी। अतः नियमानुसार वसूली की कार्यवाही न किये जाने के कारण रु. 142.52 लाख न वसूले जाने का प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता हैं।

STAN

izLrj 1- :0 30-00 yk[k dk bdkb;ksa dks dsUnzh; iwWath fuos"k lgk;rk dk vfu;fer ykHk Lohd`r fd;k tkukA

As per the para 11 of Central Capital Investment Subsidy scheme,2003 if the central Government/State government concerned is satisfied that the subsidy or grant to an industrial unit has been obtained by misrepresentation as to an essential fact, furnishing of false information the central government/state government may, after giving opportunity to the unit concerned of being heard, ask the unit to refund the grant or subsidy already received.

Further as para 14 after the receiving the grant or subsidy, each industrial unit shall submit Annual Progress Report to the State Government about its working for a period of 5 years after going into production.

As per Govt. of India guidelines/Instructions cash payment have not been considered. Plant&Machinery acquired after the registration and with-in one year from the date of commencement of commercial Production only has been considered. In bank finance cases fixed capital investment in plant& machinery as per bank appraisal has been considered as eligible for calculating CCISS. On the basis of the above, the amount of 15% subsidy to which you are entitled in determined at Rs. you are entitled in determined at Rs. 30.00 lakhs.

Government of India Ministry of Commerce & Industry Department of Industrial Policy & promotion (special Package Section) No.3(2)2008-SPS Dated 25th January 2011 sub:- Clarification on Grant of Central Capital Investment Subsidy to an Industrial Undertaking Company or Group setting up more than one unit in the state of Uttarakhand-regarding that units located in the same khasra number/location/Industrial area would be eligible for the subsidy if they are separate and distinct and registered as such under the relevant State/Central Laws.

vkuUn d`'.kk gksVy izk0 fy0 dk"kkhiqjA

QSyhDlhVc bUVjuss"kuy fy0 dk"khiqjA

:nziqj fV;wc bf.M;kWa izk0 fy0 flMdqy iUruxjA

,l0,y0th0 czkbZV ok;j izk0 fy0 iUruxjA

dYi r:i vkVks ikVZ dk"khiqjA

f"ko gfj lykboqM tliqj A

ikjys fcLdqV izk0 fy0 flrkjxtA

fl}kFkZ isij fy0 ¼;wfuV&2½dk"khiqjA

dsUnzh; iwWath miknku ;kstuk izkIr bZdkbZ;ksa dh i=kofy;ksa ds voyksdu djus ij ik;k x;k fd bZdkbZ;ksa }kjk vius dkjksckj ls lEcfU/kr dsUnzh; mRikn ,oa lhek "kqYd foHkkx esa iathd`r ,oa jkT; ds okf.kZT; dj foHkkx esa iathd`r djus lEcfU/kr vfHkys[k izLrqr gh ugh fd;s gSA ftlls ;g Kkr gks lds fd bZdkbZ fdu dk;ksZ ds djus gsrq dsUnzh; miknku lgk;rk dh ekWax :0 30-00 yk[k dj jgh gSA rFkk bdkbZ ds }kjk fdl izdkj dk dk;Z fd;k tk jgk gS]vFkok fd;k tk;sxkA tSls%& bdkbZ fofuekZ.kd]lsok {ks+=]gksy lsy]Vs`MlZ];k tkWac odZ bR;kfn dk;Z djus ds fy;s izFkd ls iathd`r gksuk vko";d gksrk gSA

bl lEcU/k esa i=koyh ds voyksdu djus ij ik;k x;k fd ,d gh dEiuh dh vyx&vyx ?kksf'kr ;wfuVksa ij dsUnzh; miknku lgk;rk ds fy;s ftyk m|ksx dsUnz esa vius dks iathd`r djkdj ;kstuk dk ykHk izkIr fd;k x;k gSA tcfd Hkkjr ljdkj ds No.3(2)2008-SPS Dated 25th January 2011 ds vuqlkj dsoy ogh bdkbZ;kWa ik=rk fu/kkZfjr dj ldrh gSa ftlds }kjk vius izFke dkjksckj ls fHkUu f}rh; bZdkbZ dks Hkh izFke bdkbZ dh rjg okf.kZT; dj foHkkx esa djksckj djus gsrq vyx ls iathd`r djk;k x;k gksA izR;sd QeZ }kjk viuh f}rh; bdkbZ dks dsUnzh; iwWath miknku lgk;rk izkIr djus gsrq izFke ls vyx dj ubZ bdkbZ crk;k rks x;k Fkk ijUrq muds dkjksckj ls lEcfU/kr vyx fjVZu tSls okf.kZT; dj foHkkx mRrjk[k.M] esa izLrqr i=koyh;ksa esa lyaXu ugh FkhA fQj fdu fdu vfHkys[kks ds vk/kkj ij bdkbZ dks u;h bdkbZ ekudj izdj.k dks funs"kky; esa dsUnzh; iwWath miknku ;kstuk dk ykHk nsus

gsrq iszf’kr fd;k x;k Fkk A dsUnzh; iwWath fuos”k lgk;rk fu;ekoyh 2003 esa mYyf[kr izko|kuksa ds foijhr FkkA

foHkkx ls bl lEcU/k esa iwNus ij crk;k x;k fd lEizs{kk ny dh vkifRr mfpr gS] Hkof’; esa lEcfU/krksa ls pkgs x;s vfHkys[k ;Fkk”kh?kz izkIr djus gsrq funsZf”kr fd;k tk;sxkA

foHkkxh; mRrj lUrks’k tud ugh gSa] D;ksfd foHkkx dk ;g dguk fd Hkfo’; esa lEcfU/krksa ls pkgs x;s vfHkys[k ;Fkk”kh?kz izkIr djus gsrq funsZf”kr fd;k tk;sxk]ls vius vki gh ;g Li’V gksrk gSa fd nkok izkIr vfHkys[kksa dh fu;ekuqqlkj tkWap fd;s fcuk gh bdkbZ;ksa }kjk izLrqr nkok izi=ksa dks ekU;rk iznku djrs gq,s nkok /kujkf”k dks laLrqr dj funs”kky; esa Lohd`fr djus gsrq izsf’kr fd;s tkrs gSA funs”kky; Lrj ij Hkh laLrqr fd;s x;s nkoksa ds izi=ksa dh tkWap fd;s fcuk gh /kujkf”k Lohd`r djus gsrq jkT; Lrj desVh ds le{k nkoksa dks izLrqr dj Lohd`fr iznku dj yh tkrh gSA tksfd vfu;fer gSA ;fn dk;kZy; ,oa funs”kky; Lrj ls nkoksa esa n”kk;s x;s O;; vfHky[kksa dh tkWap lEcfU/kr okf.kT; dj foHkkx ls nkok lLrqr djus ls iwoZ ;k nkok /kujkf”k Lohd`r djus ds mijkUr ijUrq bdkb;ksa dks Hkqxrku djus ls iwoZ djk;h x;h gksrh]rks rqfViw.kZ ,oa feF;k dFku izLrqr dj nkok izkIr bdkbZ;ksa dks dsUnzh; miknku /kujkf”k dk vfu;fer Hkqxrku ugh fd;k tkrkA tksfd foHkkxh; mnklhurk dks n”kkZrk gSA blfy;s izFke bdkbZ;ksa dh f}rh; ,oa vU; ;wfuVksa ls ftudk okf.kZT; dj foHkkx esa ,d gh fVu la[;k gSa tksfd viuh izFke bdkbZ;ksa ds fy, gh tkWac odZ dk dk;Z dj jgh gSA mudh Hkqxrku dh x;h dsUnzh; miknku /kujkf”k dh owlyh 18 izfr”kr C;kt lfgr Hkw&jktLo dh HkkWafr djds jktdks’k esa tek fd;s tkus ;ksX; gSA

vr% izdj.k laKku esa yk;k tkrk gSA

STAN

प्रस्तर 2- निर्माण कार्य के सापेक्ष विभाग एवं कार्यदायी संस्था के मध्य एमओयू गठित न किया जाना।

कार्यालय जिला उद्योग केंद्र, उधमसिंह नगर की लेखापरीक्षा के दौरान पाया कि जिला उद्योग केंद्र भवन/आवास निर्माण एवं फासिलिटेशन कोंसिल एवं विजिनेसप्रमोशन सेंटर के भवन निर्माण हेतु क्रमश: Rs 20.00 लाख तथा Rs 5.91 लाख कुल धनराशि Rs 2591000.00 ट्रेजरी चैक संख्या 207814 के द्वारा दिनांक 06-12-2012 को अधिशाषी अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण सेवा, विकास भवन, रुद्रपुर(उधमसिंह नगर) को उपलब्ध कराई गई। अभिलेखो मे एमओयू, अनुबंध एवं कार्य मे की गई वास्तविक व्यय से संबन्धित लेखा, यथा अंतिम भुगतान विपत्र प्रमाण एवं निर्मित संपत्ति हस्तांतरण प्रमाणपत्र नहीं थे, जिस कारण हस्तगत धनराशि के सापेक्ष वास्तव मे कितना व्यय किया गया और एमओयू न होने के कारण भवन एवं अन्य कार्य कब पूर्ण किया गया, सुनिश्चित नहीं होता है अर्थात किन शर्तों के साथ एवं कितनी अवधि मे कार्य पूर्ण किया जाना था, भी सुनिश्चित नहीं होता है। इसे इंगित करने पर विभाग ने उत्तर मे बताया कि, "एमओयू कराए जाने हेतु कोई निर्देश प्राप्त नहीं है। फिर भी भविष्य में कोई भी निर्माण कार्य करवाये जाने पर एमओयू की जाएगी। " विभाग के उत्तर से स्पष्ट है कि विभाग के द्वारा कार्यदायी संस्था के साथ एमओयू नहीं किया गया है अतः रु0 25.91 लाख के निर्माण कार्य के सापेक्ष विभाग एवं कार्यदायी संस्था के मध्य एमओयू गठित न किए जाने का प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग-III

(इस भाग में विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण निम्न प्रारूप में अंकित किया जाय)
विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-II 'अ' प्रस्तर संख्या	भाग-II 'ब' प्रस्तर संख्या
08-09 15/2012-13	Part-II'A'-01 01	1,2 01

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्याः

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तर संख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण	अनुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी	अभ्युक्ति
15/2012-13 08-09	भाग-II 'अ' प्रस्तर- 01 भाग-II 'ब' प्रस्तर-01, भाग-II 'अ' प्रस्तर-01 भाग-II 'ब' प्रस्तर-01,02		विभाग की आख्या तथ्यात्मक नहीं है अतः प्रस्तर तथावत रखा जा सकता है। से संबंधित आख्या प्रस्तुत नहीं की गयी।	

भाग-IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

-शून्य-

भाग-V

आभार

1. कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु **महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र, रूद्रपुर (उधमसिंह नगर)** तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है। तथापि **लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गयेः**
   (i) शून्य
2. **सतत् अनियमितताएः**
   (i) शून्य

3. **लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया**

क्रम सं0	नाम	पदनाम
(i)	श्री वाई.सी. पाण्डेय	महाप्रबन्धक जिला उद्योग केन्द्र, उधम सिंह नगर

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति **महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र, रूद्रपुर (उधमसिंह नगर)** को इस आशय से प्रेषित कर दी जायेगी कि अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे वरिष्ठ उप महालेखाकार/उप महालेखाकार (संबंधित क्षेत्र का नाम) को प्रेषित कर दी जांय।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी
आर्थिक क्षेत्र-2